



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 25 मार्च, 2002/4 चैत्र, 1924

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 25 मार्च, 2002

संख्या 1-26/2002-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक

संख्यांक-4) जो आज दिनांक 25 मार्च 2002 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

2002 का विधेयक संख्यांक 4.

जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2002

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से विधि द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुवंशिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सहित शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाओं का सृजन करने की इच्छा रखते हुए रजिस्ट्रीकृत न्यास, जय प्रकाश सेवा संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग के लिए करार किया है, जिसका, अर्थों में से मुख्य उद्देश्य, समस्त स्तरों पर शिक्षा सुविधाओं का सृजन करना है ; और

इस सहयोग का प्रयोजन, हिमाचल प्रदेश राज्य में आजीवन शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाओं सहित स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर तथा आचार्य सम्बन्धी (डॉक्टोरल) स्तरों की तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करना था ; और

राज्य सरकार, सम्यक् विचार के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि न्यास, उपरोक्त करार के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में इच्छुक और समर्थ है तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना के मुख्य भाग के सृजन में वस्तुतः पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया गया है ; और

इसमें इसके पश्चात् आने वाले प्रयोजनों के लिए जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय की स्थापना करने को समीचीन समझा गया है ।

भारत गणराज्य के तिरपनवे वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 है ।
- (2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे सरकार, राजनय में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।
- (3) विश्वविद्यालय वाकनाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “विद्या परिषद्” से, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ख) “कुलाधिपति” से, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है ;
- (ग) “संकायाध्यक्ष” से, विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ ।

परिभाषाएं ।

- (घ) "कार्य परिषद्" से, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;
- (ङ) "वित्त समिति" से, विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (च) "निधि" से, विश्वविद्यालय की निधि अभिप्रेत है;
- (छ) "शासकीय परिषद्" से, विश्वविद्यालय की शासकीय परिषद् अभिप्रेत है;
- (ज) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (झ) "प्रबन्ध न्यासी" से, जय प्रकाश सेवा संस्थान, नई दिल्ली का प्रबन्ध न्यासी अभिप्रेत है;
- (ञ) "सदस्य" से, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का सदस्य अभिप्रेत है ;
- (ट) "अधिसूचना" से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ठ) "विहित" से, विनियमों, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ड) "प्रतिकूलपति" से, विश्वविद्यालय का प्रतिकूलपति अभिप्रेत है;
- (ढ) "मान्यता प्राप्त संस्था" से, विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई या न्यास द्वारा प्रारम्भ की गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बन्धित कोई उच्च ज्ञान संस्था अभिप्रेत है ;
- (ण) "रजिस्ट्रार" से, विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (त) "विनियम", "परिनियम", "अध्यादेश" से, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियम, परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत है ;
- (थ) "शिक्षक" के अन्तर्गत आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक या विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण, अनुसंधान के संचालन या शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी अन्य पद पर इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति है और इसके अन्तर्गत कोई "मान्यताप्राप्त शिक्षक" भी होगा ;
- (द) "न्यास" से, जय प्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली अभिप्रेत है ;
- (ध) "विश्वविद्यालय" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है; और
- (न) "उप-कुलपति" से, विश्वविद्यालय का उप-कुलपति अभिप्रेत है ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार, अधि-सूचना द्वारा नियत करे, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्व-विद्यालय स्थापित किया जाएगा जो कुनाधिपति, प्रतिकुलपति, उप-कुलपति, शामकीय परिषद्, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और रजिस्ट्रार से गठित होगा । विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।

(2) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम का, शाश्वत उत्तराधिकार और शक्ति सहित सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा, और उस पर उसके नाम से वाद लाया जा सकेगा ।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा या के विरुद्ध सभी वादों और अन्य विधिक कार्य-वाहियों में, अभिवचन रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों में सभी प्रक्रियाएं और कार्यवाहियां रजिस्ट्रार को जारी और उस पर शामिल होंगी ।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय धाकनाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा ।

4. अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार क्रियाकलापों द्वारा ज्ञान, प्रज्ञान और बोध का प्रसार, सृजन और अभिवृद्धि करना तथा उच्चतर मानकों की तकनीकी शिक्षा प्रदान करना विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे । उद्देश्य ।

5. विश्वविद्यालय की, इसके विभिन्न अधिकारियों और प्राधिकरणों द्वारा या उनके माध्यम से प्रयुक्त या अनुपालित की जाने वाली निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।

(क) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में नई पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों में नई रीति के प्रयोग करना ;

(ख) अध्यापन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषय विहित करना और उपाधियां/डिप्लोमें प्रदान करने के लिए शिक्षा पद्धति में लचीलेपन की व्यवस्था करना ;

(ग) किसी विधि के अधीन किसी कानूनी निकाय द्वारा मान्यता यदि अपेक्षित हो, के अध्यधीन परीक्षाएं संचालित कराना और ऐसी उपाधियां, डिप्लोमें या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना, जैसी विनियमों में अधिकथित की जाएं ;

(घ) दूरवर्ती शिक्षा प्रोग्रामों सहित शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए भारत तथा विदेश में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी में प्रतिष्ठित केन्द्रों के साथ सम्बन्ध विकसित करना और बनाए रखना ;

- (ङ) उद्योग, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों या किसी अन्य स्त्रोत से निधियां प्राप्त करना तथा, यथास्थिति, दाताओं, उपकारकों, वसीयतकर्ताओं या अन्तरकों से उपहार या अनुदान या उपकृतियां या वसीयतें और स्थावर या जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्तियां प्राप्त करना;
- (च) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के उन्नयन के लिए, विश्वविद्यालय से सम्बन्धित या उसमें निहित सम्पत्ति से किसी भी रीति में, जो आवश्यक समझी जाए, संव्यवहार करना ;
- (छ) ऐसी फीसों की मांग करना और प्राप्त करना जैसी विनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं;
- (ज) अनुसंधान और उच्चतर शिक्षा के संचालन में अन्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहकार करना ;
- (झ) विश्वविद्यालय के कार्यकरण और मामलों के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाली नीति के प्रश्नों पर निर्णय लेना ;
- (ञ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय लेना ;
- (ट) ऐसे अधिकारी, अध्यापक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ;
- (ठ) किसी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय के अध्यापन, अनुसंधान और परामर्श के कार्य में लगा है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और प्राध्यापक के पदनाम या कोई अन्य समतुल्य पदनाम, प्रदत्त करना ;
- (ड) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्योग के साथ संयोजन विकसित करना ;
- (ढ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूसरे कन्द्रों/निगमित सेक्टर तथा अन्यों के पाठ्यक्रमों को प्रत्यायित करना ;
- (ण) दूरवर्ती शिक्षा सहित शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विकसित देशों में सूचना प्रौद्योगिकी में प्रतिष्ठित केन्द्रों के साथ द्वियुगमी व्यवस्था विकसित करना और बनाए रखना ;
- (त) न्यास द्वारा स्थापित और चलाए गए किसी अन्य केन्द्र/संस्थान को, इसके शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के घटक निकाय के रूप में सम्बद्ध करना और इसे, प्राप्तिकर्ता द्वारा विहित अपेक्षाओं को पूर्ण करने पर, उपाधियां, डिप्लोमों और प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रदान करने के लिए स्वीकार करना ; और
- (थ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य कृत्य और कार्य करना, जो आवश्यक हों ।

6. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और अपनी शक्तियों के प्रयोग तथा अपने कृत्यों के अनुपालन में विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ग, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या मूलवंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा भेदभाव न किया जाना।

7. इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाए, विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियाँ, हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में प्रयोक्तव्य होंगी। विश्वविद्यालय की अधिकारिता।

8. (1) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। कुलाधिपति।

(2) कुलाधिपति को, प्रतिकुलपति के परामर्श से, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय, इसके भवनों, पुस्तकालयों और उपस्करों तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए किसी भी संस्थान और इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन कार्य या विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी अन्य कृत्य का निरीक्षण करवाने का और उसी रीति में विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय की बाबत जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण करने या जांच करवाए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच पर उपस्थित रहने या सुने जाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों की बाबत, कुलपति को सम्बोधित कर सकेगा और कुलपति, शासकीय परिषद् को, ऐसे परामर्श सहित, जैसा कुलाधिपति ने उस पर कार्रवाई किए जाने को प्रस्तावित किया हो, कुलाधिपति के विचार संसूचित करेगा।

(5) शासकीय परिषद्, कुलपति के माध्यम से, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गई किसी कार्रवाई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, की संसूचना कुलाधिपति को देगा।

9. (1) न्यास का प्रबन्ध न्यासी, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति होगा। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। विश्वविद्यालय के अधिकारी।

(2) परिनियमों द्वारा विहित रीति में नियुक्त एक कुलपति होगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा तथा कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) एक संकायाध्यक्ष होगा जो ऐसी रीति में और ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों सहित, नियुक्त किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) एक रजिस्ट्रार होगा जो शासकीय परिषद्, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के गैर-सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसी रीति और ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों सहित नियुक्त किया जाएगा जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(5) एक वित्त अधिकारी होगा जो वित्त समिति का गैर-सदस्य सचिव होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसे परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(6) ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जा सकेंगे।

विश्व- 10. शासकीय परिषद्, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और ऐसे विद्यालय के अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण विहित किए जा सकेंगे, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होंगे :

परन्तु यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से सदस्य निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के अन्य निकाय का सदस्य बनने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

शासकीय परिषद्। 11. (1) शासकीय परिषद्, विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय होगी और इसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जा सकेंगे।

(2) शासकीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) प्रतिकुलपति .. अध्यक्ष।
- (ख) प्रतिकुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले न्यास के दो सदस्य .. सदस्य।
- (ग) सहयोगी विश्वविद्यालयों के दो प्रतिनिधि .. सदस्य।
- (घ) कुलाधिपति द्वारा प्रतिकुलपति के परामर्श से, नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशिष्ट शिक्षाविद/वृत्तिक .. सदस्य।
- (ङ) प्रतिकुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वित्त, विधि और प्रबन्ध इत्यादि अन्य विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो विशेषज्ञ .. सदस्य।
- (च) विश्वविद्यालय उप-कुलपति .. सदस्य।
- (छ) अन्य संस्था/न्यास की विशेष प्रयोगशाला का एक अध्यक्ष .. सदस्य।
- (ज) चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष .. सदस्य।
- (झ) सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), सचिव (शिक्षा) और सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार .. सदस्य।

(अ) प्रतिकूलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उद्योग के तीन प्रतिनिधि

.. सदस्य ।

(3) रजिस्ट्रार, शासकीय परिषद् का गैर-सदस्य सचिव होगा ।

12. (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और इसकी शक्तियाँ एवं कृत्य, पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों का गठन और पदावधि ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जा सकेगी । कार्य परिषद् ।

(2) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रबंध और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगी ।

13. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी, इसका गठन और पदेन सदस्यों से भिन्न, इसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जो परि- विद्या परिषद् ।
नियमों द्वारा विहित की जा सकेगी ।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अध्वधीन विद्या परिषद् को नियन्त्रण और साधारण विनियम की शक्ति होगी या, और विश्वविद्यालय के भीतर अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को बनाए रखने के लिए दायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा इसे प्रदत्त या इस पर अधिरोपित किए जाएं । इसे, कार्य परिषद् को, सभी शैक्षणिक मामलों पर परामर्श देने का अधिकार होगा ।

14. (1) निम्नलिखित सदस्यों से गठित एक संस्था-उद्योग सहवर्तिता परिषद् होगी, अर्थात् :— संस्था-उद्योग सहवर्तिता परिषद् ।

(क) प्रतिकूलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई व्यक्ति .. अध्यक्ष ।

(ख) न्यास द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति .. सदस्य ।

(ग) विश्वविद्यालय का उप-कुलपति .. सदस्य ।

(घ) प्रतिकूलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उद्योग से दो व्यक्ति ... सदस्य ।

(2) रजिस्ट्रार, संस्था-उद्योग सहवर्तिता परिषद् का गैर-सदस्य सचिव होगा ।

(3) संस्था-उद्योग सहवर्तिता परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे—

(i) प्रमुख प्रतिष्ठित सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर कम्पनियों की प्रयोगशालाओं की विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता स्थापित करना;

(ii) विश्वविद्यालय के संकाय (विभाग)/विद्यार्थियों के लिए कारवार के स्रोत उद्गम करना;

(iii) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय बाजार में विश्वविद्यालय की क्षमता/शक्ति पर परामर्श देना; और

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा जीव सूचनात्मक उपक्रमण तैयार और आरम्भ करना।

परिनियम।

15. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम, निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या इनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (i) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकरणों और अन्य निकायों की सदस्यता के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं, इसके सदस्यों की नियुक्ति और उनका हटाया जाना तथा उससे सम्बन्धित अन्य विषय;
- (ii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (iii) विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति, सेवा शर्तें, शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (iv) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द के कल्याण के लिए पेन्शन या भविष्य निधि का गठन और बीमा योजना की स्थापना;
- (v) निबन्धन और शर्तें जिन के अधीन अन्य संस्थाएं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकेंगी;
- (vi) विश्वविद्यालय का प्रशासन, अध्येतावृत्ति, पुरस्कार इत्यादि की संस्थापना, उपाधियों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियाँ प्रदत्त करना और डिप्लोमें और प्रमाण-पत्र प्रदान करना; और
- (vii) कोई अन्य विषय जो विश्वविद्यालय के मामलों के उचित और प्रभावी प्रबन्ध तथा संचालन के लिए आवश्यक हों और जो इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित किया जाना है या परिनियमों द्वारा उपबन्धित किया जा सकेगा।

परिनियम
किस प्रकार
बनाए
जाएंगे।

16. (1) प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा और उसकी एक प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

(2) शासकीय परिषद्, समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या इसके पश्चात्, इस धारा में उपबन्धित रीति में बनाए गए परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु शासकीय परिषद्, किसी विद्यमान प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई ऐसा परिनियम तब तक नहीं बनाएगी या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्ताव पर राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी भी प्रकार की राय लिखित रूप में होगी और उस पर शासकीय परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ऐसा परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या परिनियमों के किसी संशोधन या निरसन के लिए प्रतिकुलपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे पुनर्विचार के लिए शासकीय परिषद् को भेज सकेगा :

परन्तु यह कि शासकीय परिषद्, विद्या परिषद् से परामर्श किए बिना, विद्या-थियों के अनुशासन, अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के स्तरमानों को प्रभावित करने वाला कोई भी परिनियम नहीं बनाएगी।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियम को तब तक कोई विधिमाम्यता नहीं होगी जब तक कि उसे प्रतिकुलपति द्वारा अनुमति न दे दी गई हो।

17. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय परिषद्, ऐसे अध्यादेश बना सकेगी जिन्हें वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, समुचित समझे और ऐसे अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (i) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक पदकों से सम्बद्ध अर्हताएं, अध्ययतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार इत्यादि प्रदान करने हेतु शर्तें ;
- (ii) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षकों की पदावधि और नियुक्ति भी है तथा छात्रों के निवास की दशाएं और उनका सम्यक् अनुशासन ;
- (iii) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार का संचालन ;
- (iv) कोई अन्य विषय जिसका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

(2) इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों का, शासकीय परिषद् द्वारा, परिनियमों द्वारा विहित रीति से, किसी भी समय संशोधन, निरसन या अभिवर्धन किया जा सकेगा।

18. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, शासकीय परिषद् के निदेश के अधीन वार्षिक तैयार की जाएगी और वह उसकी एक प्रति हिमाचल प्रदेश विधान सभा के पटल रिपोर्ट पर रखवाएगी।

19. विश्वविद्यालय की, न्यास द्वारा उसके नाम पर स्थापित और विश्वविद्यालय सामान्य द्वारा परिचालित एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,— निधि।

(क) विश्वविद्यालय के संग्रह निधि के लिए, न्यास द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले, दो वर्ष की अवधि के भीतर, दो बराबर किस्तों में, पांच करोड़ रुपए ;

(ख) फीमों से सम्बन्धित इसकी आय और विन्यास ;

(ग) न्यास या सरकार द्वारा दिया गया आवर्तक अंशदान या अनुदान, यदि कोई हो ; और

(घ) कोई अन्य अंशदान या अनुदान ।

लेखे और
संपरीक्षा ।

20. (1) विश्वविद्यालय के लेखे, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर विश्वविद्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(2) लेखों की संपरीक्षा हो जाने पर, उन की एक प्रति, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, रजिस्ट्रार द्वारा, शासकीय परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी ।

आकस्मिक
रिक्तियों
का भरा
जाना ।

21. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया है और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

रिक्तियों के
कारण कार्य-
वाहियों का
अविधिमान्य
न होना ।

22. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं ।

कठिनाइयों
को दूर
करना ।

23. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र, में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, और जो कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक प्रतीत हों ।

संक्रमण-
कालीन
उपबन्ध ।

24. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिकूल-पति, कुलाधिपति के अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अधीन, अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त या अनुपालित की जाने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन तब तक कर सकेगा जब तक इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा यथा उपबन्धित ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं आता ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आधुनिक अतियोगी परिवेश में नियोजक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऐसे उत्पादों की ओर उन्मुख हो रहे हैं जो तेजी से बदलती हुई सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा में सहजता से अनुकूलनीय हो सकें। वे न तो विकासशील पाठ्यक्रम या उपाधि कार्यक्रमों की परम्परागत पद्धतियों का इन्तजार करने के इच्छुक हैं, न ही वे शिक्षा की वर्तमान पद्धति को यथा रूप स्वीकार करने के इच्छुक हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विश्वव्यापी स्तर पर तेजी से बदलते दृश्यलेख में, यह आवश्यक है कि इसके स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा की अत्यन्त गतिशील पद्धति को लाया जाए। जबकि सरकारी क्षेत्र में भी, सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अपेक्षित स्तर के उप-व्यवसायों को उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, यह महसूस किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी उपयोजन सेक्टर में, प्रशिक्षित जनशक्ति की विशिष्ट मांग को ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर में निजी पहल को सक्रियता से प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इससे उच्चतर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित स्त्रोत भी अनुपूरित होंगे। यह सर्व-विदित है कि आज के प्रौद्योगिक विश्व में परिवर्तन दर अत्यन्त तेज है और जब तक, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा पद्धति का, इन परिवर्तनों के साथ-साथ चलना स्वीकार नहीं किया जाता, ये अनावश्यक हो जाएंगी। त्वरित अप्रचलनोन्मुखता के दृष्टिगत इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी उपलब्धि में सुधार और विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तैयार करना, अतिरिक्त ज्ञान और जीविका के लिए नई दर्शन शक्ति को अभिव्यक्ति देना है।

यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उन पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के लिए, विश्वविद्यालय की स्थापना को अनुज्ञात करने का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य सुधार और नूतन विषय (नई पद्धति) की अभिवृद्धि करना है। यह तकनीकी शिक्षा में सुधार तथा यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार के प्रयासों को अनुपूरित करता है कि विद्यार्थी दक्षता और ज्ञान के उस स्तर को, जो उन्हें चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक और उद्योग में मान्यता प्राप्त दक्षता स्तरमानों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, अर्जित करें। प्रस्तावित विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा, अनिर्वक्त ज्ञान तथा उच्च प्रवीणता और उच्च वेतन जीविकाओं में अवसरों के व्यापक क्षेत्र के लिए तैयार करेगा। यह विधेयक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उन उच्च श्रेणी प्रोग्रामों को सकेन्द्रित करते हुए, जो शैक्षणिक और व्यवसायिक शिक्षा को एकीकृत करते हैं और चुनौतिपूर्ण शैक्षणिक, व्यवसायिक और तकनीकी स्तरमान की प्राप्ति की सक्रियता में अभिवृद्धि करते हैं, विश्वविद्यालय की महत्ता के केन्द्र के रूप में स्थापना करने में प्राईवेट सेक्टर निवेश (निजी क्षेत्र विनिधान) को सुकर करता है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय, उद्योग में प्रबल अनुभव रखने वाले तथा उद्योग के समस्त पहलुओं का बोध रखने वाले विद्यार्थी तैयार करेगा। इसका उद्देश्य सम्भावनाओं वाले नियोजकों को अन्तर्वलित करना तथा माध्यमिक और परामाध्यमिक शिक्षा के बीच प्रबल सम्बन्ध स्थापित करना है। एक विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान के रूप में यह प्रौद्योगिकी के प्रयोग का विकास, सुधार तथा विस्तार करने तथा अध्यापकों, विद्यार्थियों और प्रशासकों के व्यावसायिक विकास की व्यवस्था करने की चेष्टा करेगा।

यह विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा स्तरमानों में निरन्तर सुधार की अभिवृद्धि करने और राज्य के लिए कार्य उत्तरदायित्व पद्धति सृजित करने के लिए भी है। जय प्रकाश सेवा संस्थान, जो कि एक रजिस्ट्रीकृत न्यास है, अपनी लागत पर विश्वविद्यालय की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण करने की प्रस्थापना करता है। इस उद्देश्य के साथ, विधेयक में यथा उपबन्धित के अनुसार कार्य के स्तरों और विश्वविद्यालय की स्थापना और इसके संचालन के लिए व्यापक विरचना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ करार हुआ है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, जय प्रकाश सेवा संस्थान नामक न्यास को, उसकी अपनी निधियों में से और इस विधेयक के अधीन इसके लिए विनिर्दिष्टतः यथा उपबन्धित से विश्वविद्यालय स्थापित करने, प्रवर्तित करने, चलाने और अनुरक्षित करने के लिए समर्थ बनाएंगे। अतः इससे राजकोष पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 15, 16 और 17 विश्वविद्यालय को, अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए परिनियम और अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2002.

**THE JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY
BILL, 2002**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to establish and incorporate a University in the name of Jaypee University of Information Technology by law and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Government of Himachal Pradesh being desirous of creating facilities for education, training and research in the emerging areas of technology including Information Technology in the State of Himachal Pradesh, entered into an agreement for collaboration with Jaiprakash Sewa Sansthan, New Delhi, a registered Trust, which has a major objective among others, of creating education facilities at all levels; and

WHEREAS the purpose of this collaboration was to establish a University for technical education for undergraduate, postgraduate and doctoral levels including facilities for life long education, training and research in the State of Himachal Pradesh; and

WHEREAS the State Government after due consideration has come to the conclusion that the Trust is willing and is capable of meeting its obligations under the aforesaid agreement and has actually invested substantial resources in the creation of major part of the infrastructure required for the setting up of the proposed University; and

WHEREAS it is deemed expedient to establish the Jaypee University of Information Technology for the purposes hereinafter appearing.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Jaypee University of Information Technology Act, 2002.

Short title
and com-
mencement.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(3) Seat of the University shall be at Wahnaghat, District Solan, Himachal Pradesh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions,

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "Chancellor" means the Chancellor of the University;

- (c) "Deans" means the Deans of the University ;
- (d) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
- (e) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (f) "Fund" means the Fund of the University;
- (g) "Governing Council" means the Governing Council of the University;
- (h) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
- (i) "Managing trustee" means the Managing trustee of the Jaiprakash Sewa Sansthan, New Delhi;
- (j) "Member" means a member of the authorities of the University;
- (k) "Notification" means notification published in the Official Gazette;
- (l) "Prescribed" means prescribed by regulations, Statutes and Ordinances;
- (m) "Pro-Chancellor" means the Pro-Chancellor of the University;
- (n) "Recognised institution" means an institution of higher learning run by the University or started by the Trust and recognised by, or associated with the University;
- (o) "Registrar" means the Registrar of the University;
- (p) "Regulation", "Statute", "Ordinances" mean respectively the regulations, Statutes, Ordinances made by the University under this Act;
- (q) "Teacher" includes a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Lecturer or any person appointed under this Act with any other designation for the conduct of training, research, or imparting education in the University and shall mean and include a "recognised teacher";
- (r) "Trust" means the Jaiprakash Sewa Sansthan, New Delhi;
- (s) "University" means the Jaypee University of Information Technology established under section 3 of this Act ; and
- (t) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University.

Estab-
lishment
and incor-
poration of
the Univer-
sity.

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification appoint, there shall be established, in the State of Himachal Pradesh, a University by the name of the Jaypee University of Information Technology, which shall consist of a Chancellor, Pro-Chancellor, Vice-Chancellor, the Governing Council, Executive Council, Academic Council and the Registrar.

(2) The University shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property, to contract and shall, by the said name, sue and be sued.

(3) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to, and served on, the Registrar.

(4) The Headquarters of the University shall be at Wahnaghat, District Solan, Himachal Pradesh.

4. The objects of the University shall be to disseminate, create and advance knowledge, wisdom and understanding, and to offer technical education of the high standards by teaching, research, training and extension activities.

Objects.

5. The University shall have the following powers and functions to be exercised and performed by or through its various officers and authorities, namely:—

Powers and functions of the University.

- (a) to conduct innovative experiments in new methods and technologies in the field of technical education in order to maintain international standards of such education, training and research;
- (b) to prescribe courses and curricula for various courses of studies and provide for flexibility in the education system for grant of degrees/diplomas;
- (c) to conduct examinations and grant such degrees, diplomas or other academic distinctions as may be laid down in the regulations, subject to recognition by any statutory body under any law, if required;
- (d) to develop and maintain relationship with centres of excellence in Information Technology in India and abroad for education, training and research including distance learning programmes;
- (e) to receive funds from industries, international organisations or any other source, and gifts or donations or benefactions or bequests or properties both moveable and immovable from donors or benefactors or testators or transferors, as the case may be;
- (f) to deal with property belonging to or vested in the University in any manner which is considered necessary for promoting the objects of the University;
- (g) to demand and receive such fees as may be laid down by the regulations;
- (h) to co-operate with other national and international institutions in the conduct of research and higher education;
- (i) to take decisions on questions of policy relating to the administration of the affairs and working of the University;
- (j) to take decisions regarding the admission of students for the courses-offered by the University;
- (k) to appoint such officers, teachers and other employees as are necessary for carrying out the functions of the University;
- (l) to confer the designations of Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Lecturer or any other equivalent designations upon any person who is engaged in teaching, research and consultancy work of the University;
- (m) to develop linkages with the industry for fulfilment of the objectives of the University;
- (n) to accredit the courses of other centres/institutions of the corporate sector and others in the area of Information Technology;

- (o) to develop and maintain twinning arrangements with centres of excellence in Information Technology in the developed countries for education, training and research including distance education;
- (p) to affiliate any other centre/institution established and run by the Trust as a constituent body of the University for the purpose of its academic programme and admitting it for the award of Degrees, Diplomas and Certificates on fulfilment of the prescribed requirements by the recipients; and
- (q) to do such other acts and things as may be necessary for the furtherance of the objects of the University.

University
not to dis-
criminate.

6. In pursuit of its objectives and in exercise of its powers and in performing of its functions, the University shall not discriminate between any persons whatsoever on the basis of caste, class, colour, creed, sex, religion or race.

Jurisdiction
of the Uni-
versity.

7. Save as otherwise provided by or under this Act, the powers conferred on the University shall be exercisable in the area comprising Himachal Pradesh.

Chancellor.

8. (1) The Governor of Himachal Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor, in consultation with the Pro-Chancellor, shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipments and of any institution run by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an enquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(3) The Chancellor shall, in every case give notice to the University, of his intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the results of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Governing Council the views of the Chancellor along with such advice as the Chancellor may have offered on the action to be taken thereon.

(5) The Governing Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken on the results of such inspection or inquiry.

Officers of
the Uni-
versity.

9. (1) The Managing Trustee of the Trust shall by virtue of the office be the Pro-Chancellor of the University and in the absence of the Chancellor, the Pro-Chancellor shall preside over the Convocation of the University.

(2) There shall be a Vice-Chancellor appointed in the manner prescribed by the Statutes who shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University and *Ex-Officio* Chairman of the Executive Council, Academic Council and Finance Committee.

(3) There shall be Deans who shall be appointed in such manner and with such powers and duties as may be prescribed by the Statutes.

(4) There shall be a Registrar who shall act as a Non-Member Secretary of the Governing Council, Executive Council and Academic Council and he shall be appointed in such manner and with such powers and duties as may be prescribed by the Statutes.

(5) There shall be a Finance Officer who shall be Non-Member Secretary of the Finance Committee and exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

(6) There shall be such other officers as may be prescribed by the Statutes.

10. The authorities of the University shall be the Governing Council, Executive Council, Academic Council, Finance Committee and such other authorities as may be prescribed by the Statutes to be the authorities of the University :

Authorities of the University.

Provided that if any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

11. (1) The Governing Council shall be the supreme body of the University and its powers and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes.

The Governing Council.

(2) The Governing Council shall have the following members, namely:—

- | | | |
|---|-----|------------------|
| (a) The Pro-Chancellor | ... | <i>Chairman.</i> |
| (b) Two members of the Trust to be nominated by the Pro-Chancellor | .. | <i>Members.</i> |
| (c) Two representatives of the collaborating Universities | ... | <i>Members.</i> |
| (d) Three distinguished academicians/professionals to be nominated by the Chancellor in consultation with the Pro-Chancellor | .. | <i>Members.</i> |
| (e) Two experts representing other disciplines such as finance, law and management etc. to be nominated by the Pro-Chancellor | .. | <i>Members.</i> |
| (f) Vice-Chancellor of the University | .. | <i>Member.</i> |
| (g) One Head of another Institute/laboratory of the Trust | .. | <i>Member.</i> |
| (h) Two Deans of the University by rotation | .. | <i>Members.</i> |
| (i) Secretary (Information Technology), Secretary (Education) and Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh | .. | <i>Members.</i> |
| (j) Three representatives of the Industry to be nominated by the Pro-Chancellor | .. | <i>Members.</i> |

(3) The Registrar shall be Non-Member-Secretary of the Governing Council.

The Executive Council.

12. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and its powers and functions, the constitution and the terms of the office of its members, other than *ex-officio* members, shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Executive Council shall be responsible for the general management and administration of the University.

The Academic Council.

13. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and its constitution and the term of office of its members, other than *ex-officio* members, shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Academic Council shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the power of control and general regulation or, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act or the Statutes and it shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

The Council of Institution-Industry Linkages.

14. (1) There shall be a Council of Institution-Industry Linkages consisting of the following members, namely:—

- | | |
|---|-------------|
| (a) A person to be nominated by the Pro-Chancellor | Chairman. |
| (b) Two persons to be nominated by the Trust | .. Members. |
| (c) Vice-Chancellor of the University | .. Member. |
| (d) Two persons from the Industry to be nominated by the Pro-Chancellor | .. Members. |

(2) The Registrar shall be the Non-Member Secretary of the Council of Institution-Industry Linkages.

(3) The powers and functions of the Council of Institution-Industry Linkage shall be—

- (i) to establish participation of laboratories of leading prestigious Information Technology/Computer companies with the University;
- (ii) to source business for Faculty/Students of the University;
- (iii) to advise on the potential of the University in National and International market; and
- (iv) to prepare and initiate Bio-informatics initiative by the University.

Statutes.

15. Subject to the provision of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (i) constitution, powers and duties of the authorities and other bodies of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities and other bodies, appointment and removal of members thereof and other matters connected therewith;

- (ii) the appointment, powers and duties of the officers of the University;
- (iii) the appointments, conditions of service, powers, and duties of the employees of the University;
- (iv) the constitution of a pension or a provident fund and the establishment of an insurance scheme for the welfare of the officers, teachers, and other employees of the University;
- (v) the terms and conditions under which other institutions may be associated with the University;
- (vi) the administration of the University, the institutions of fellowships, awards and the like, the conferment of degrees and other academic distinctions and grant of diplomas and certificates; and
- (vii) any other matter which is necessary for the proper and effective management and conduct of the affairs of the University and which by this Act is to be or may be provided by the Statutes.

16. (1) The first Statute shall be made by the State Government and a copy thereof shall be laid before the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

Statutes.
how to be
made.

(2) The Governing Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes so made in the manner hereinafter provided in this section :

Provided that Governing Council shall not make any Statute or any amendment of the Statute affecting the status, powers or constitution of any existing authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion on the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Governing Council.

(3) Every such Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of the Statutes shall require the approval of the Pro-Chancellor who may assent thereto or withhold assent or return it to the Governing Council for reconsideration :

Provided that no Statute shall be made by the Governing Council affecting the discipline of students and standards of instruction, education and examination except in consultation with the Academic Council.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Pro-Chancellor.

17. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Governing Council may make such Ordinances as it deems appropriate for the furtherance of the objects of the University and such Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

Ordinances

- (i) the admission of the students, the courses of study and the fees thereof, the qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the conditions for grant of fellowships, awards and the like ;

- (ii) the conduct of examinations, including the terms of office and appointment of examiners and the conditions of residence of students and their general discipline ;
- (iii) conduct of the business of the authorities of the University and those of the committees appointed by them; and
- (iv) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided by the Ordinances.

(2) Ordinances made may be amended, repealed or added to at any time by the Governing Council in the manner prescribed by the Statutes.

Annual
report.

18. The Annual report of the University shall be prepared under the direction of the Governing Council and a copy of the same shall be caused to be laid on the Table of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

General
Fund.

19. The University shall have a General Fund set up by the Trust in the name of the University and operated by the University to which shall be credited,—

- (a) rupees five crore within a period of two years in two equal instalments to be provided by the Trust for the Corpus Fund of the University;
- (b) its income relating to the fees and endowments;
- (c) recurring contribution or grants, if any, made by the Trust or the Government ; and
- (d) any other contributions or grants.

Accounts
and Audit.

20. (1) The accounts of the University shall, once at least in every year and at intervals of not more than fifteen months be audited by the Chartered Accountants of the University.

(2) A copy of the accounts when audited, together with the audit report shall be submitted by the Registrar to the Governing Council.

Filling of
casual va-
cancies.

21. All casual vacancies amongst the members (other than *ex-officio* members) of any authority or body of the University shall be filled up as soon as convenient, by the person or body who appointed, elected or co-opted the member whose place has become vacant and the person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Proceedings
not to be
invalidated
by vacan-
cies.

22. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies amongst its members.

Removal of
difficulties.

23. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make

such provisions not inconsistent with the purposes of this Act, as appear to it to be necessary for removing the difficulty.

24. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes, the Pro-Chancellor may, with the approval of the Chancellor and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of the Act and the Statutes and for that purpose may exercise any powers or perform any duties, which by this Act and the Statutes are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence as provided by this Act and the Statutes.

Transitory
provisions.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the modern competitive environment, employers in the field of Information Technology are looking for products who may easily adapt to the fast changing Information Technology education. They are not willing to wait for traditional way of developing curricula or degree programmes, nor are they willing to accept the existing system of education as it is. In the fast changing scenario of Information Technology worldwide, it is necessary that a very dynamic system of Information Technology education is put in place. While efforts are being made in the Government sector also for providing Information Technology related avocations of the requisite standards, it is felt that private initiative in this sector needs to be actively encouraged in view of the specific requirements of the trained manpower in Information Technology applications sector. This would also supplement the resources required for the purpose of higher Information Technology education. It is well known that the rate of change in today's technological world is extremely fast and unless the Information Technology education system is allowed to keep pace with these changes, the same will be rendered redundant. The main objective of this Bill is to give expression to the new vision to improve student achievement and preparing students for graduation and postgraduation level of technical education, further learning, and careers in view of the fast pace of obsolescence.

This Bill proposes to allow the setting up of a University for imparting Information Technology related courses which aims at to promote reform and innovation. It seeks to supplement Government efforts to improve technical education and to ensure that students acquire the level of skills and knowledge they need to meet challenging academic and industry-recognized skill standards. The proposed University will prepare students for postgraduation education, further learning, and a wide range of opportunities in high-skill and high-wage careers. This Bill facilitates private sector investment in setting up a University as a centre of excellence in the field of technical education focusing on high quality programmes that integrate academic and vocational education and actively promote attainment of challenging academic, vocational and technical standard. The proposed University will provide students with strong experience in, and understanding of all aspects of an industry. Its objective will be to involve potential employers and provide strong linkages between secondary and postsecondary education. As a specialised institution, it will seek to develop, improve and expand the use of technology and provide for professional development of teachers, students and administrators.

The Bill also seeks to promote continuous improvement in Information Technology education standards, and create a performance accountability system to the State. The Jaiprakash Sewa Sansthan, which is a registered Trust proposes to set up, run and maintain the University at their own cost. With this objective an agreement to ensure levels of performance, and broad framework to set up the University and to run it, as provided for in the Bill, has been arrived at with the Government of Himachal Pradesh.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:

The....., 2002.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, when enacted will enable the Trust namely Jaiprakash Sewa Sansthan to establish, set-up, run and maintain the University out of its own funds and as provided for specifically under this Bill. As such there will be no financial implications on the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 15, 16 and 17 of the Bill empower the University to make Statutes and Ordinances to discharge its functions under the Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

